भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2787

दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु कदम

2787# श्री नीरज शेखरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): महोदय, सरकार ने पर्यटन, डिजिटल/दूरसंचार कनेक्टिविटी, सड़क/हवाई/समुद्री कनेक्टिविटी, अवसंरचनात्मक विकास, शासन सुधार आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन को इसके बहुगुणक प्रभाव के कारण एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएनआई) ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और द्वीपों में पर्यावरण-पर्यटन, क्रूज पर्यटन, सांस्कृतिक, विरासत, साहसिक पर्यटन और पर्यटक सर्किट जैसी विभिन्न पर्यटन गतिविधियों/पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने पक्षी अवलोकन, कारवां पर्यटन, लक्जरी टेंट, खगोल पर्यटन और हाउसबोट पर्यटन के लिए नवोन्मेषी नीतियां बनाई हैं। इसके अलावा, होटल आवास की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शहीद द्वीप, एवेस, लॉन्ग एवं स्मिथ द्वीप में पर्यावरण-पर्यटन परियोजनाएं और श्री विजयपुरम में मेगापोड रिसॉर्ट की ब्राउनफील्ड परियोजना पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही हैं। घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, स्वराज द्वीप स्थित राधानगर बीच (Beach) को ब्लू

फ्लैग बीच (Blue Flag Beach) के रूप में प्रमाणित किया गया है, जबकि पांच बीचों (Beaches) पर पर्यटन अवसंरचना का उन्नयन किया गया है।

इसी प्रकार, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप ने मिनिकॉय, कदमत और सुहेली द्वीपों पर पीपीपी मॉडल के तहत अपनी तरह के पहले लैगून विला विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। बंगारम द्वीप तथा थिन्नाकरा में पर्यटकों की लंबे समय से चली आ रही आवास की मांग को पूरा करने के लिए, बंगारम में 50 लग्जरी टेंटेड स्टे (Tented Stay) तथा थिन्नाकरा में 100 टेंट अब चालू कर दिए गए हैं। मिनिकॉय स्थित थुंडी बीच (Beach) तथा कदमत बीच (Beach) को ब्लू फ्लैग बीच (Blue Flag Beach) का दर्जा मिल चुका है और दो अन्य बीचों (Beaches) को भी इसी प्रकार के प्रमाणीकरण के लिए चिन्हित किया गया है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाने और नागरिकों को इसके फायदे पहुंचाने के लिए, चेन्नई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (CANI) ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना के चालू होने से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) में डिजिटल/दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारतनेट के अंतर्गत, सभी ब्लॉक, ग्राम पंचायतें और जनजातीय परिषदें जुड़ चुकी हैं। इसी तरह, कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह (KLI) सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना (KLI-SOFC परियोजना) ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप के सभी आबाद द्वीपों को सबमरीन केबल के माध्यम से जोड़ा गया है। दोनों द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के लिए सैटेलाइट ट्रांसपोंडर के माध्यम से अतिरिक्त कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की गई है।

द्वीपों के लिए हवाई संपर्क के महत्व को देखते हुए, संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने श्री विजयपुरम में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवनिर्मित आधुनिक टर्मिनल भवन को चालू कर दिया है, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 50 लाख यात्रियों को संभालने की है। द्वीपों के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए श्री विजयपुरम से कार निकोबार, डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, कमोर्ता, कचल, चौरा, टेरेसा, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और कैंपबेल बे के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए, संघ राज्यक्षेत्र ने डिगलीपुर, कार निकोबार तथा कैंपबेल बे को 19 सीटों वाले फिक्स्ड विंग (Fixed Wing) विमान से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, समुद्री संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए एम.वी. सिंधु (MV Sindu), एम.वी. नालंदा (MV Nalanda), 150-यात्री क्षमता वाले चार हार्बर क्राफ्ट और 50-यात्री क्षमता वाले तीन पोत शामिल किए गए हैं; इसके साथ ही, जेट्टी अवसंरचना में सुधार तथा STARS ई-टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से डिजिटल यात्री सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी तर्ज पर, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप ने

मुख्य भूमि (कोच्चि, गोवा और बेंगलुरु) से अगाती द्वीप के लिए नियमित उड़ानों की सुविधा सुनिश्चित की है। द्वीपों के बीच संपर्क के लिए नियमित फेरी सेवाएं संचालित की जा रही हैं तथा कवारत्ती, अगाती, कदमत, कल्पेनी तथा किल्तान में सीप्लेन की सफल परीक्षण लैंडिंग भी की जा चुकी है।

चूंकि अवसंरचना आर्थिक विकास की नींव रखती है, इसलिए द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में सड़कें, पत्तन, घाट, पत्तन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल शासन आदि जैसी कई अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

दोनों द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में, सरकार ने समावेशी विकास, आजीविका सृजन, अवसंरचना निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सशक्त निगरानी तंत्र के साथ प्रमुख योजनाओं का प्रभावी और परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। इन योजनाओं का उपयोग कनेक्टिविटी, पेयजल और स्वच्छता कवरेज, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, आवास, मत्स्य पालन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की आजीविका, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इस समन्वय-आधारित दृष्टिकोण ने अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार किया है, रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है और सामाजिक कल्याण परिणामों को बढ़ाया है, विशेष रूप से दूरस्थ द्वीपीय बस्तियों में।

उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, कारोबार की सुगमता और उदारीकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ अनुपालन का बोझ काफी कम कर दिया गया है, जिससे निवेश का भरोसा बढ़ा है और आर्थिक गतिविधियां व्यापक हुई हैं। पूंजी और ब्याज सब्सिडी प्रदान करके निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की गई हैं।

द्वीपीय संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्य क्षेत्र एवं ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न पहलें की गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत मत्स्य परिवहन वाहनों, जलीय कृषि फार्मों, हैचरियों, फीड मिलों, कियोस्क तथा मूल्य संवर्धित उद्यमों के लिए 268 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे लगभग 500 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है; मायाबंदर में स्मार्ट एकीकृत मत्स्य बंदरगाह, बाथुबस्ती में थोक-सह-खुदरा मत्स्य बाजार का विकास, कृत्रिम रीफ (Artificial Reefs) की स्थापना तथा जंगलीघाट, होपटाउन, दुर्गापुर, चिड़ियाटापू और शोल बे में पाँच जलवायु-लचीले तटीय मत्स्यजीवी ग्रामों की स्थापना; खुले समुद्र में केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती तथा मोती उत्पादन को प्रोत्साहन; निवेश, निर्यात तथा बाजार संपर्क को

बढ़ावा देने के लिए फिशरीज इन्वेस्टर मीट एवं रिवर्स बायर-सेलर मीट का आयोजन; मत्स्य विस्तार सेवाओं एवं मत्स्य अवतरण (फिश लैंडिंग) आँकड़ों के संग्रहण हेतु सागर मित्रों को स्वीकृति; तथा फिश लैंडिंग केन्द्रों, एचडीपीई फ्लोटिंग जेटियों, आइस प्लांटों एवं शीत भंडारों के माध्यम से मत्स्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण; आधुनिक मत्स्य बाजारों की स्थापना, यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं के उन्नयन, डीप फ्रीजर की खरीद, एकीकृत एक्वापार्क की स्थापना, समुद्री खाद्य परिवहन निकासी सुविधा तथा Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) कार्यक्रम के अंतर्गत मालभाड़ा सब्सिडी सहायता को स्वीकृति।

इसी प्रकार, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में भी अनेक पहल की गई हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत 388 लाभार्थी-उन्मुख परियोजनाओं का पूर्ण किया जाना; चेतलत में समुद्री शैवाल हैचरी के साथ समुद्री शैवाल क्लस्टर तथा कदमत में बीज बैंक की स्थापना; मछुआरों से प्रत्यक्ष खरीद के लिए 42 मत्स्य संग्रहण पोतों को अनुमति प्रदान करना; तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 2,368 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करना और 74 मत्स्य सहकारी समितियों का परिचालन।

सरकार की इन पहलों से द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास हुआ है। भारत सरकार का प्रयास है कि द्वीपीय संघ राज्यक्षेत्रों को सुशासन और विकास का प्रेरणा-स्रोत (Role Model) बनाया जाए।

******